लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 अप्रैल 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -39

"किसी की अधिक प्रशंसा करना उसे धोखा देना है।"

: जयशंकर प्रसाद

सुनो धरती के बोल, पानी है अनमोल

5

अयोध्या नगरी में 'गाली बंद घर' अभियान

6

सूरजकुंड मेले में दिखा संस्कृति का संगम

8

भ्रष्टाचार पर होगा कड़ा प्रहार

विशेष प्रतिनिधि

शासन-प्रशासन में 'तीन दो पांच' करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के प्रति हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। ऐसा करने वाले लोगों का पता लगाने, पकड़ने व सजा दिलाने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा विजिलेंस का डिविजन स्तर तक विस्तार किया जाएगा ताकि व्यवस्था में तह तक निगरानी रखी जा सके।

हरियाणा निवास में प्रदेशभर के जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए डिविजनल लेवल पर 6 स्वतंत्र इकाइयां गठित की जाएं।

डिविजनल लेवल पर इन इकाइयों की प्रोसीक्यूशन सैंक्शन डिविजनल कमिशनर के पास रहेगी। इन इकाइयों का मुख्य कार्य ग्रुप बी, सी व डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मिली एक करोड़ रुपए राशि तक की शिकायतों की जांच करने की जिम्मेदारी होगी। ग्रुप-ए श्रेणी के कर्मचारियों व एक करोड़ से अधिक राशि की शिकायतों की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पहले की तरह करता रहेगा।

विजिलेंस विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में पहले ही जिला विजिलेंस टीम कार्यरत हैं। सरकार ने इन्हें भी मजबूत किया है। पिछले 2 महीनों में इनके पास 98 शिकायतें आई हैं, जिनकी जांच जारी है।

सरकार ने पहली बार इस तरह की हाई पावर कमेटी का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव, हरियाणा करेंगे। इसके अलावा इसमें राजस्व वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) तथा निदेशक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। भ्रष्टचार की शिकायतों के निवारण जल्द से जल्द करने के लिए इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी।

ऑनलाइन सिस्टम से लगा अंकुश

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए दंडात्मक, सुधारात्मक और चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले लोग भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करते थे लेकिन हमने इसे पकड़ने का काम किया है। सरकार का मुख्य ध्येय है कि भ्रष्टाचार करने वालों के मन में भय का माहौल बने। इसके लिए सरकार ने आनलाइन सिस्टम तैयार किया है।

चाणक्य का उदाहरण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरित्र निर्माण के लिए चाणक्य से जुड़ी 'लैंप नेशनल ट्रेजरी' कहानी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बार चाणक्य लैंप की रोशनी में सरकारी काम कर रहे थे। अचानक से उनसे मिलने के लिए एक दोस्त आ गया। चाणक्य ने उन्हें रुकने के लिए कहा, थोड़ी देर बाद चाणक्य ने अपना वह लैंप बुझा दिया और दूसरा लैंप जलाकर अपने दोस्त से बातचीत शुरू कर दी। यह देख दोस्त ने लैंप बुझाने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सरकारी खजाने के तेल से जल रहे लैंप में सरकारी काम कर रहा था। अब आपसे मेरी मुलाकात व्यक्तिगत है, इसलिए मैंने अपना लैंप जलाया है, जिसमें मेरे निजी कोष से खरीदा गया तेल इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें ऐसे राष्ट्रीय चरित्र की जरुरत है, जिनसे पूरा देश प्रेरणा ले सके।

मानव संसाधन विभाग बना

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हमने एक नए विभाग मानव संसाधन (एचआर) के गठन करने का भी निर्णय लिया है। इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों से जुड़ा रिकॉर्ड, उनकी ट्रांसफर, उनके ऊपर चल रहे मामले व सेवानिवृत के बाद पेंशन से जुड़े मामले रहेंगे। यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा। फिलहाल इसका सचिव आईएएस चंद्रशेखर खरे को बनाया गया है।

अंत्योदय को समर्पित रहा बजट

विधानसभा का बजट सत्र 'अंत्योदय' को समर्पित रहा। सत्र में न केवल अधिकांश माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखने का अवसर मिला बल्कि उनके द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा भी दिया गया।

प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने 'सबकी सलाह पर सबका बजट' पेश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश के सभी गरीब परिवार आत्मनिर्भर बनें तथा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

22 मार्च तक चला बजट हरियाणा के इतिहास का सबसे लंबा सत्र रहा। विधायकों को बोलने का खूब मौका मिला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर आठ घंटे 44 मिनट चर्चा हुई। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के 20 विधायकों ने 44 मिनट, जजपा के पांच विधायकों ने 64 मिनट, कांग्रेस के 15 विधायकों ने दो घंटे 14 मिनट, तीन निर्दलीय विधायकों ने 26 मिनट और इनेलो विधायक अभय चौटाला ने 12 मिनट तक अपनी बात रखी।

विधायकों ने कुल 81 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए जिनमें से 21 को स्वीकृत किया और चर्चा कराई गई। राज्य सरकार की ओर से कुल 18 विधेयक सदन में रखें जिनमें से 15 पारित हो गए। दो बिलों को चयन समिति को भेजा गया है जबकि एक बिल वापस ले लिया गया।

लोकसभा की तर्ज़ पर चले विधानसभा के बजट सत्र में अधिकांश सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखा गया। सरकार की ओर से उन्हें गंभीरता से सुना गया और विकास का भरोसा दिया गया।

बजट सत्र की करीब 12 बैठकें बुलाई गई और सदन में 50 घंटे तक चर्चा हुई। जिसमें 15 अहम विधेयक पारित हुए। प्रदेश के समग्र एवं समान विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस बार भी 'सबकी सलाह पर सबका बजट' तैयार किया। बजट पर बहुमूल्य सुझाव लेने के लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्र के 477 हितधारकों के साथ बजट पूर्व आठ बैठकें की, जिनमें एम्स और मेदांता के डॉक्टर भी शामिल हुए।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

गौरैया

मुंडेर पर या आंगन में उड़ती गौरैया अपनी चीं-चीं की मधुर आवाज से उसी परिवार का सदस्य होने का एहसास दिलाने का प्रयास करती है। जैसे छोटा बच्चा भूख को शांत करने के लिए रोटी-रोटी करता है उसी प्रकार गौरैया भी अन्न के दानों की खातिर कभी गीत सुनाती तो कभी नृत्य करती है। पौ फटने से पूर्व वह अपनी चहचाहट से घर के सदस्यों का प्रातः वंदन कराना कभी नहीं भूलती।

कुछ अर्से से यह प्राकृतिक संगीत कम हो गया है। घटते पेड़-पौधे, विस्तृत होते पक्के मकानों की पक्की छत, खेतों में यूरियायुक्त फसलें व अन्य बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या कम हो चली है। अनुमान के मुताबिक 60 फीसदी गौरैया कम हो गई हैं। इनके संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 20 मार्च को 'विश्व गौरैया दिवस' मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 20 मार्च 2010 को हुई थी।

समूहों में रहना पसंद करने वाली गौरैया एक बार में दो से चार अंडे देती है तथा 5 से 7 वर्ष तक जीवित रहती है। यह घोंसला बनाकर रहती है। भोजन की तलाश में 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मीलों का सफर भी कर लेती हैं। जरूरत पड़ने पर पानी पर तैर लेती हैं। इसका वजन 30 से 40 ग्राम तक होता है। गौरैया हमारे लिए मात्र पक्षी नहीं हैं, जीवन का हिस्सा हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों के बीज खाकर उन्हें दूर तक फैलाने का कार्य ये चिड़िया करती आई हैं।

हरियाणा सरकार की ओर से गौरैया के संरक्षण के लिए शिवालिक हिल्स के गांव जोधपुर व गुरुग्राम के गांव भौंडसी में एक एक एकड़ में प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र प्रस्तावित हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा की ओर से लोगों को आह्वान किया गया है कि वे घरों में ऐसे झरोखे निर्मित करें जहां चिड़िया घोंसला बना सकें। छत, मुंडेर या आंगन में अनाज के दानें डालें व पेयजल की व्यवस्था करें। इसके अलावा पौधारोपण को जुनून बनाने का प्रयास करें।

-मनोज प्रभाकर

संपादकीय

औषधीय खेती की सुगंध

औषधीय पौधों की खेती की ओर अब निरंतर रुझान बढ़ रहा है। इससे होने वाले दोहरे मुनाफ़े ने किसानों को व्यावहारिक रूप से आकर्षित किया है। अम्बाला के समीप गांव बड़ी बस्सी में 'साधविका आर्गेनिक एंड हर्बल साइंस' की ओर से हुई पहलकदमी के आकर्षक परिणाम मिल रहे हैं। एक प्रगतिशील किसान डॉ. वीपी सिंह की देखरेख में 120 एकड़ भूमि पर हो रही यह औषधीय पौधों की खेती आसपास के किसानों को भी आकर्षित कर रही है।

कभी देख आएं इस कृषि फ़ार्म को, सुख भी मिलेगा, प्रेरणा भी और एक रचनात्मक सुगंध भी। वैसे भी फ़सलों के परम्परागत चक्र से बाहर आने का यह अनूठा प्रयोग है। गेहूं और धान की फसल के बीच के लगभग तीन माह के समय में तुलसी की फसल तैयार की जाती है। इससे किसानों को 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ की आमदनी हो जाती है। बागवानी विभाग द्वारा जिले में एमआईडीएच स्कीम के तहत विभिन्न मदों में अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत विभाग द्वारा एरोमेटिक प्लांट की खेती करने पर 6400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। इसी गांव बड़ी बस्सी में ऐरोमेटिक प्लांट पर 40 एकड़ में अनुदान राशि 25 हजार छह सौ रुपए की गई है।

गांव के किसान राजेश कुमार को भी एक लाख 65 हजार रुपए जारी किए जा चुके हैं। किसान राजेश कुमार ने बताया कि बागवानी विभाग से प्रेरित होकर एरोमैटिक फसल शुरू की है।

औषधीय पौधों से तैयार उपज के लिए अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार हो रहा है। करीब छह करोड़ रुपए की राशि से तैयार हो रहे इस प्लांट में डिस्टिलेशन, एक्सट्रेशन एंड स्टोरेज की सुविधा होगी। इसमें कोल्ड रूम तथा कोल्ड स्टोरेज भी तैयार किया जा रहा है। यहां पर औषधीय पौधों की फार्मिंग के साथ-साथ मेडिसनल प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाई जा रही है। इस यूनिट में आसपास के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। 60 लोग इस समय यहां काम कर रहे हैं। इनमें से 25 महिलाएं हैं। यूनिट में अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी इत्यादि औषधीय पौधों का अर्क और पाउडर तैयार होगा। औषधीय पौधा, पामा रोजा, इत्र बनाने के काम आता है। सट्रिनेला आलआउट, कच्छुआ छाप/मोस्किटी रेपेलेंट बनाने के काम आता है। लेकिन ग्रास, साबुन, फ्रागेंस और लेमन ग्रास टी बनाने के भी काम आता है। इस खेत में इंटर 'ॉपिंग विधि से भी खेती की जाती है। आप भी चाहें तो इस प्रयोगधर्मिता से लाभान्वित हो सकते हैं।

- डॉ. चन्द्र त्रिखा

वरदान साबित हो रही एबुलेंस सेवाएं

दुर्घटना अथवा आपात चिकित्सा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एंबुलेंस सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। अस्पताल पूर्व देखभाल और त्वरित परिवहन से काफ़ी हद तक लोगों की जानें बचाती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में आपातकालीन सेवाओं और एम्बुलेंस सेवाओं को और अधिक सहज बनाने पर ध्यान दिया है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कुल 3,8 6,946 रोगियों को एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गई।

कॉल अटेंड कर पहुंचाई मदद

जिला हिसार नंबर-एक के रूप में रहा, जिसने 27,550 कॉलों का उत्तर दिया है, अंबाला 24,691 कॉलों के साथ नंबर-दो रहा और सिरसा 23,137 कॉल के साथ तीन नंबर पर रहा। गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने के मामले में पलवल नंबर-एक पर रहा, जिसने 14,151 गर्भवती महिलाओं को पहुंचाया, कुरुक्षेत्र नंबर-दो पर रहा जिसने 11,327 को और जिला जींद नंबर-तीन पर रहा, जिसने 8,770 गर्भवती महिलाओं को पहुंचाने का काम किया।

वर्तमान में 635 एम्बुलेंस

राज्य में वर्तमान में 635 एम्बुलेंस चल रही हैं जिसमें 161 एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस, 170 बेसिक लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस, 268 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस और 30 किलकारी एम्बुलेंस और 6 नियोनेटल केयर एम्बुलेंस शामिल हैं। इन एम्बुलेंसों का प्रबंधन लगभग सभी जिलों में संचालित विकेंद्रीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा किया जाता है।

निःशुल्क परिवहन सेवाएं

गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच और प्रसव के लिए घर/घटना स्थल से निकटतम सरकारी स्वास्थ्य सुविधा तक आपात स्थिति में निःशुल्क परिवहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, प्रसव के बाद घर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं, सड़क किनारे दुर्घटना के शिकार लोगों, प्रसव के बाद के छह सप्ताह तक के प्रसव के बाद के मामलों, बीमार शिशुओं और पांच वर्ष तक के बच्चों, मानसिक आपात स्थिति, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिक और उनके आश्रित सैन्य अस्पताल/ निकटतम सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के लिए सेवायें दी जा रही है। जिले के भीतर स्वास्थ्य सुविधा और अंतर सुविधा के लिए परिवहन / तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान भी की जा रही हैं।

अटल जननी वाहिनी सेवा

'अटल जननी वाहिनी सेवा' के तहत 188 रोगी परिवहन एम्बुलेंस को गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पतालों/एसडीएच/ सीएचसी/ पीएचसी में ले जाने के लिए तैनात किया है, जहां भारी डिलीवरी लोड को चिह्नित किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य का लक्ष्य हमेशा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के उद्देश्य से सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए ' जननी सुरक्षा योजना', ' जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान' स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में 47 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) की खरीद और तैनाती भी की है। साथ ही 26 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस और 16 नवजात देखभाल एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

विजय वर्धन बने मुख्य सूचना आयुक्त

सेवानिवृत आईएएस विजय वर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सेवानिवृत आईएएस सत्यवीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने हरियाणा निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों अधिकारियों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। दोनों अधिकारियों ने हिंदी में शपथ ली।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

ग्राम संरक्षक योजना

सरकारी कार्यों के साथ समाज सेवा भी करेंगे अधिकारी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार 'ग्राम संरक्षक योजना' के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4,000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस योजना के तहत अधिकारी एक-एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गांवों के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे बताया।

अधिकारियों को लोगों की सेवा करने के इरादे से इस क्षेत्र में निष्ठा और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने राज्य में जनकल्याण और विकास के लिए सरकारी अधिकारियों के इस अनूठे सहयोग की एक नई पहल की है। जैसे निजी क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप-पीपीपी है, उसी प्रकार इसे गवर्नमेंट-कम्युनिटी पार्टनरशिप (जीसीपी) कहा जाएगा, जिसमें अधिकारी अपने कार्यालय के नियमित कार्यों के अलावा गांवों के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस वेबिनार के लिए विशेष रूप से एक गैर-कार्य दिवस को चुना है क्योंकि ये कार्य गैर-कार्य दिवस पर ही किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह उनके सरकारी कार्य का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज सेवा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को महीने में कम से कम एक बार अपने गोद लिए गांव का दौरा करना होगा और इसके विकास की निगरानी करनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को 'सबका साथ-सबका विश्वास' की विचारधारा का पालन करते हुए इस योजना पर समाज सेवा के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।

समृद्धि और हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के अलावा, सरकार राज्य के लोगों की सुख-समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने विस्तार से बताया कि राज्य के 'हैप्पीनेस इंडेक्स' से लोगों की समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें अपनी रैंकिंग बढ़ाने की ज़रूरत है और 'ग्राम संरक्षक योजना' पर काम करके ये अधिकारी राज्य के 'हैप्पीनेस इंडेक्स' में सुधार के लिए प्रमुख योगदान देंगे।

सरकारी अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारी बने हिस्सा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित सभी लोग गांवों के विकास में योगदान दें तो राज्य और अधिक तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि संरक्षक वेबसाइट intrahry.gov.in पर पंजीकरण कर पंचायतों का चयन कर सकते हैं। यदि वे गोद लिए गए गांव को बदलना चाहते हैं तो संबंधित एडीसी से संपर्क किया जा सकता है। राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी और लोग, जो गांव के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे हरियाणा स्वयंसेवी कार्यक्रम की वेबसाइट-samarpan.haryana.gov.in पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

राज्य सरकार अंबाला में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह की स्थापना करेगी जिसके वर्ष 2023-24 तक शुरू होने की उम्मीद है।

डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 8,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के दायरे को 2021-22 से चार लाख रुपए तक आय सीमा के साथ सभी वर्गों के लिए बढ़ाया गया है।

जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़ी सज़ा का प्रावधान

विधानसभा बजट सत्र में कुल 15 विधेयक पारित

प्रदेश में अब जबरन धर्म परिवर्तन के मामले अपराध की श्रेणी में होंगे तथा दोषियों को कड़ी सज़ा की सिफारिश की जाएगी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 को यथा संशोधित पारित किया गया।

विधेयक के तहत झूठ बोलकर, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।

धर्म-परिवर्तन-यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म-परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को धर्म-परिवर्तन की घोषणा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी।

धर्म-परिवर्तन का आयोजन करने का आशय रखने वाला कोई भी धार्मिक पुरोहित अथवा अन्य व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आयोजन स्थल की जानकारी देते हुए पूर्व में नोटिस देगा। नोटिस की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह 30 दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट जांच करके तय करेगा कि धर्म-परिवर्तन का आशय धारा-3 की उल्लंघना है या नहीं है। यदि वह इसमें कोई उल्लंघना पाता है तो आदेश पारित करते हुए धर्म-परिवर्तन को अस्वीकार कर देगा। जो अपराध कहलाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धोखे से या किसी तरह का लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। इस विधेयक का मकसद जबरदस्ती होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रण करना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चार साल में 6 जिलों में धर्म परिवर्तन 127 एफआईआर दर्ज हुई। यमुनानगर, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। इस वजह से विधेयक लाया गया है। मुख्यमंत्री ने चंगाई सम्मेलन, ग्लोबल पीस जैसे एनजीओ समेत प्रदेश से जुड़े कई उदाहरण देकर जबरदस्ती होने वाले धर्म परिवर्तन के मामले पटल पर रखे।

कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित

हरियाणा विधान सभा बजट सत्र में कुल 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, किसान कल्याण प्राधिकरण विधेयक, यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन विधेयक, जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, लोक उपयोगिता परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, विनियोग (संख्या 2) विधेयक, सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) विधेयक, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक और हरियाणा मानव अंग प्रतिरोपण (विधिमान्यकरण) विधेयक शामिल हैं।

अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक

हरियाणा राज्य में अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं से संबंधित विधि को समेकित करने तथा निर्माण कार्य में अग्नि निवारण व जीवन सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाने से संबंधित मामलों के लिए हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022 पारित किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 एवं हरियाणा लॉजिस्टीक पॉलिसी आदि के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए यह विधेयक लाया गया है।

विधेयक में अग्निशमन के नियमों का उलंघन्न करने वालों को दंड का प्रावधान भी है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को तीन मास तक का कारावास अथवा 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तो भवन के प्रति वर्ग मीटर 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की राशि का भुगतान करना होगा।

लोक उपयोगिता परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक

प्रदेश में लोक-उपयोग के लिए सड़कें, रास्ते, नालियां इत्यादि के लिए कुछ लोगों ने उदारतापूर्वक भूमि प्रदान की थी। इन संस्थापनाओं पर सार्वजनिक धन खर्च किया गया है। उन्होंने लम्बी अवधि तक बिना किसी आपत्ति के जमीन के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दी। लेकिन वर्तमान में भूमि की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाने से कुछ व्यक्तियों अथवा संस्थाओं ने यह भूमि वापिस मांगनी शुरू कर दी। इस विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था लोक-उपयोगिता में विघ्न डालने, परिवर्तन करने या उसे नष्ट करने का हकदार नहीं होगा और न ही लोक-अधिकार तथा लाभ के लिए कोई दावा करेगा। यह विधेयक उन लोक-उपयोगी संस्थापनाओं, जैसे कि सड़कें, रास्ते, नहरें, नालियां आदि पर लागू होगा जो इसे लागू करने की तिथि को 20 वर्ष या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हैं।

किसान कल्याण प्राधिकरण विधेयक

प्रदेश में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को नवगठित किया गया है। यह संशोधन इस प्राधिकरण का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जा रहा है। इसके अनुसार सरकार प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रधान सचिव के रैंक का अधिकारी होगा या फिर कृषि क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। उसे प्राधिकरण के कोष से सरकार द्वारा निर्धारित मासिक वेतन व भत्ते दिए जाएंगे। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक या निदेशक के रैंक का जबकि संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाणा सिविल सेवा सेवा का अधिकारी होगा।

यांत्रिक यान संशोधन विधेयक

टोल सुविधाओं का रखरखाव हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) अधिनियम, की धारा 7 (2) के तहत निर्धारित है, जो अस्पष्ट है। अनुच्छेद धारा 7 (2) के मौजूदा खंड को संशोधित किया गया है ताकि इसे और अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके। अब इस अधिनियम के संशोधन के अनुसार जो व्यक्ति टोल टैक्स मांगता है, संग्रहण करता है या उसे रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वह सभी सडक़ अवसंरचनाओं का अच्छा रख-रखाव करेगा और उन्हें इंजीनियरी कार्य के अनुसार बनाए रखेगा। इनमें पुल, सुरंगें, पार-पथ, संपर्क सड़कों या नई सड़कों के हिस्से अथवा बाईपास आदि शामिल हैं।

यह संशोधन राज्य में टोल टैक्स देने वालों के लिए अच्छे रख-रखाव वाली सड़कें और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए किया जा रहा है।

जल संसाधन प्राधिकरण विधेयक

पानी के पुनः उपयोग और पुनरावर्तन सहित राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के लिए लागू हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया है।

इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को विनियमित करना है। प्राधिकारी भूतल पर उपलब्ध जल और उपचारित अपशिष्ट जल के अत्यधिक उपयोग के लिए खपत के आधार पर उपयुक्त दरें निर्धारित करेगा। प्राधिकारी सरकार को घरों, उद्योगों या वाणिज्यिक संस्थापनाओं के लिए जल की खुदरा दरों की सिफारिश भी करेगा।

हरियाणा विनियोग विधेयक

मार्च, 2023 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 195429,93,71,329 रुपए के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग(संख्या 2) विधेयक, 2022 पारित किया गया है।

सदाचारी बंदी विधेयक

पैरोल प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। जैसे पहले जिन कैदियों का खुद का मकान है, केवल उन्हें ही तीन वर्ष में एक बार मकान मरम्मत हेतू चार सप्ताह तथा जिन कैदियों के पास खेती-बाड़ी की जमीन है, उन्हें ही खेती के लिए एक वर्ष में छह सप्ताह तक पैरोल प्रदान करने के प्रावधान हैं। अब ये शर्त हटा दी गई है। ऐसे कैदी जो एनडीपीएस अथवा राजद्रोह अथवा हत्या के साथ बलात्कार अथवा हत्या के साथ लूट अथवा फिरोती या जबरन वसूली के अपराध में दण्डित हो, उन्हें फरलो प्रदान नहीं की जायेगी ।

अब अपराधों की श्रेणी एवं बन्दियों के जेल में आचरण के आधार पर प्रतिभूति राशि का प्रावधान किया गया है। किसी सामान्य श्रेणी के बन्दी के लिए यह राशि एक लाख रुपए से तीन लाख रुपए तक होगी। वहीं कट्टर श्रेणी के बन्दियों हेतू यह राशि कम से कम दो लाख रुपए से पांच लाख तक होगी।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक

हरियाणा सरकार द्वारा 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटे को खत्म करने एवं राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा से कम करने के उद्देश्य से हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था।

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी विशेष वर्ष में प्रचलित वित्तीय मानकों के साथ सरेखित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को आगे संशोधिन करने के लिए हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया है ।

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक

हरियाणा सरकार द्वारा मानव अंगों को निकालने, उनके भण्डारण और प्रतिरोपण के विनियमन के लिए तथा मानव अंगों के वाणिज्यिक संव्यवहार की रोकथाम के लिए मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 लागू किया गया है।

-संवाद ब्यूरो

एसीईएस स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स हिंदू ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स समारोह में हरियाणा को 'श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार' प्राप्त हुआ है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य के लिए आठ अन्य श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किया।

राज्य सरकार की महाग्राम योजना के तहत 132 गांवों में पेयजल आपूर्ति में वृद्धि, सीवरेज प्रणाली और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

विश्व जल दिव

सुनो धरती के बोल

मनोज प्रभाकर

पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी की एक-एक बूंद अनमोल है। गर्मी का आगाज़ हो चुका है, जल की खपत बढ़ेगी। कहीं-कहीं से जल संकट की खबरें भी आएंगी। सर्वविदित है कि मांग के अनुसार भू पर जल की उपलब्धता नहीं है। बहुत से इलाकों में तो पेयजल को लेकर त्राहि-त्राहि मच जाती है। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि समुद्र किनारे रहने वालों के भी कंठ सूखे रह जाते हैं।

हरियाणा के संदर्भ की बात करें तो यहां के अनेक ब्लॉक का जमीनी पानी तेजी से खारा हो रहा है। जिसकी प्रमुख वजह भूजल का अत्यधिक दोहन है। राज्य सरकार ने पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जल प्रबंधन संबंधी अनेक योजनाएं शुरु की हैं। पानी के दुरुपयोग को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि जल प्रबंधन पर सामूहिक सभागिता का दृष्टिकोण आवश्यक है। निःसंदेह जल संकट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सबसे जरुरी है पानी का व्यर्थ न बहाना।

मनोहर लाल सरकार ने जल संरक्षण को लेकर अनेक योजनाओं पर पहल की है। भूजल की कमी को रोकने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू करना, मेरा पानी-मेरी विरासत,

शामिल है।

फिलहाल दो बड़ी चुनौतियां हैं, पहली अंबाला कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ के क्षेत्रों में पानी की कमी और दूसरी राज्य भर में जलभराव की समस्या। यह चिंता का विषय है कि घग्गर क्षेत्र भी वर्तमान में पानी की कमी का सामना कर रहा है।

रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग और निष्क्रिय कुओं के माध्यम से रिचार्जिंग जैसी योजनाओं के माध्यम से पानी की कम खपत करने वाली गतिविधियों को चलाना हैं। जल-भराव को रोकने के लिए अपनाई जा सकने वाली विभिन्न रणनीतियों में उप-सतह जल निकासी, सूक्ष्म सिंचाई, नमक सहन करने वाली फसलें लगाना, वनीकरण को प्रोत्साहित करना और सतह और भूजल का उचित उपयोग करना

इस समग्र प्रयास को वित्तीय मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र को 4,554.39 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से 33.9 प्रतिशत अधिक है।

सरकार का लक्ष्य भूजल संरक्षण

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि घटता भूजल एक आपात स्थिति है और इसे किसी भी कीमत पर संभालना होगा। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, डॉ. सतबीर कादियान और प्रमोद जैन को विशेष रूप से बधाई दी जिन्होंने राज्य में रणनीतिक रूप से अटल भूजल योजना पर कार्य किया है।

प्राधिकरण सतही जल, उपचारित जल और भूजल के लिए कार्य कर रहा है। विशेषकर भूजल संरक्षण उसका लक्ष्य है। प्राधिकरण ने राज्य के सभी गांवों को भूजल तालिका के आधार पर सात अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 1948 गांवों को भूजल की अत्यधिक कमी वाले गांवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां जल स्तर की गहराई 30.01 मीटर और इससे अधिक के बीच है, 1093 गांवों को भूजल की मध्यम कमी वाले गांवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां जल स्तर की गहराई 20.01 मीटर से 30.0 मीटर के बीच है। इस बीच, 333 गांवों को संभावित जल भराव वाले गांवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां जल स्तर की गहराई 1.51 से 3.0 है और 88 गांवों को गंभीर रूप से जल भराव वाले गांवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां जल स्तर की गहराई 0.0 से 1.5 मीटर है। सरकार ने गांवों का जल स्तर के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए प्राधिकरण की सराहना की है। प्राधिकरण जल पुनर्भरण और संरक्षण के लिए द्विवार्षिक योजना पर बल दे रहा है।

जल शक्ति अभियान

हरियाणा ने पानी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ते हुए, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सभी जल निकायों की मैपिंग और जियो-टैगिंग की है। इमेजरी के आधार पर कुल 37,353 जल निकायों (23,894 प्राकृतिक और 12,957 मानव निर्मित) की पहचान की गई, जिसके बाद गांव-वार सर्वेक्षण किया गया। छवियों पर गूगल अर्थ का उपयोग करके सीमांकन भी किया गया था, और कुल 28,505 जल निकाय पाए गए थे। राज्य के कुल 16,348.66 किमी नहर/नाली नेटवर्क को 64,044.53 एकड़ के कुल कवरेज के साथ मैप किया गया था। मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग के लिए कुल 5,066 संरचनाओं की पहचान की गई और उन्हें सूचीबद्ध किया गया।

प्रत्येक जिले के लिए जिला जल संरक्षण योजना तैयार कर जल शक्ति अभियान केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इनमें जिले की सामान्य जानकारी, इसकी जल प्रोफ़ाइल, पानी की उपलब्धता, पानी की आवश्यकता/मांग और संरक्षण के लिए रणनीतिक कार्य योजना, सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता और विभाग-वार कार्य योजना/रणनीति शामिल हैं।

मेरा पानी, मेरी विरासत

जल संरक्षण रणनीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है। जहां किसानों को पानी की खपत वाले धान के अलावा अन्य फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं कई योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी को बचाने और उपचारित पानी के पुनः उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

ऐसे किसान जो पिछले वर्ष अपने धान के कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र में मक्का, कपास, बाजरा और दलहन जैसी वैकल्पिक फसलें उगाकर धान के अलावा अन्य फसलें उगाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 7,000

ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा ने शत-प्रतिशत खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायत का दर्ज़ा हासिल किया है तथा 422 ग्राम पंचायतों ने 'ओडीएफ प्लस' का दर्ज़ा भी हासिल किया है।

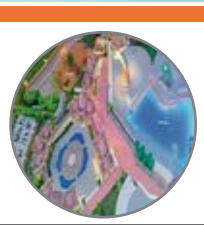

कुरुक्षेत्र में 205 करोड़ रुपए की लागत से एक थीम पार्क स्थापित किया जाएगा जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए महाभारत के युद्ध को प्रदर्शित किया जाएगा।

वस पर विशेष

ा, पानी है अनमोल

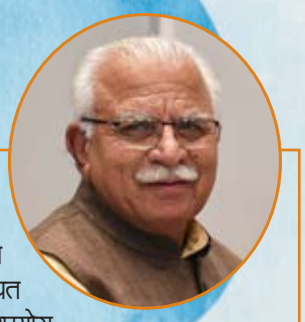

जल संरक्षण, प्रबंधन, पुनः उपयोग, पुनर्भरण और पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य में जल द्विवार्षिक 2021-2023 मनाया जा रहा है। जल प्राधिकरण एक स्थायी जल संसाधन व्यवस्था स्थापित करने और इसके विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और कुशल उपयोग के लिए काम कर रहा है जो भूजल एवं सतही जल के सुप्रबंधन के लिए आवश्यक है।

- मनोहर लाल

रुपए प्रति एकड़ प्रदान किया जाता है। उन्हें ऐसे किसी भी नए क्षेत्र में धान की खेती करने की अनुमति नहीं है जहां पिछले वर्ष के दौरान धान नहीं उगाया गया था। 50 एचपी इलेक्ट्रिक मोटर से नलकूप चलाने वाले किसानों को धान उगाने की अनुमति नहीं है।

किसानों को और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि मक्का, बाजरा और दलहन जैसी सभी विविध फसलों को एम.एस.पी. पर खरीदा जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने वैकल्पिक विविध फसलों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए 85 प्रतिशत अनुदान देने का भी वादा किया है।

सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा

सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार सहायक बुनियादी ढांचे पर खर्च का 85 प्रतिशत वहन करती है जबकि किसानों को लागत का केवल 15 प्रतिशत ही देना पड़ता है। इस वर्ष, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत सब्सिडी के रूप में 1,214 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

नहर नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए, नए समानांतर लाइन चैनल का निर्माण और पश्चिमी यमुना नहर का पुनः निर्माण, विस्तार नहर, समानांतर दिल्ली शाखा, हांसी शाखा, जवाहरलाल नेहरू नहर शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की योजना रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की पंपिंग मशीनरी की क्षमता और दक्षता में सुधार करने की भी है।

नूंह और गुरुग्राम जिलों के लिए पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार ने 200 क्यूसिक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है और 175 की मौजूदा क्षमता से 475 क्यूसिक की क्षमता के साथ गुड़गांव जल आपूर्ति (जीडब्ल्यूएस) चैनल की रीमॉडलिंग भी की है।

अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग

यदि हम अपशिष्ट जल के उपचार और उपयोग के लिए खुद को तैयार नहीं करते हैं तो जल संरक्षण अर्थहीन हो जाएगा। स्वच्छ जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गैर-पीने के उद्देश्यों के लिए बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। 1,967 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल उत्पन्न करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं।

अटल भूजल योजना

उत्तरी भाग में शिवालिक पहाड़ियाँ और दक्षिणी हरियाणा में अरावली पहाड़ियाँ प्रमुख जलसंग्रह क्षेत्र हैं। इन पहाड़ियों में पानी के कई झरने और स्रोत मौजूद हैं जो मानसून के दौरान पानी ले जाते हैं। जल प्रवाह के संरक्षण और उपयोग के लिए शिवालिक पहाड़ियों और अरावली पहाड़ियों में चेक डैम की योजना बनाई गई है।

यमुना नदी की सहायक नदियों रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी पर जल आपूर्ति में सुधार के लिए अपस्ट्रीम स्टोरेज डैम के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल दिसंबर में रेणुका बांध की आधारशिला रखी थी। इन चेक डैम की कुल भंडारण क्षमता लगभग 37.36 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) होगी।

भूजल को वर्षा जल से रिचार्ज करने की दृष्टि से 39.66 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 रिचार्जिंग बोरवेल और शाफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। 2022-23 में 5,000 रिचार्ज बोरवेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के रूप में चिन्हित 14 जिलों की 1,669 ग्राम पंचायतों में समुदाय के नेतृत्व वाले स्थायी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अटल भूजल योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ 224 हैक्टेयर मीटर की भंडारण क्षमता के साथ 388 करोड़ रुपए के आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जल जीवन मिशन

हरियाणा ने केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया है और 19 जिलों में घरों में पाइप से जलापूर्ति का काम पूरा किया है। शेष तीन जिलों जींद, पलवल और नूंह में काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 2024 की अनुमानित समय-सीमा से दो साल पहले हर पात्र घर को पाइप से जलापूर्ति का वादा पूरा होगा। सरकार ने पेयजल आपूर्ति बढ़ाने, सीवरेज सिस्टम बिछाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए महाग्राम योजना शुरू की है। इस कार्य म के तहत 132 गांवों की पहचान की गई है।

जल संसाधन प्राधिकरण

राज्य के कुछ हिस्सों में पानी की कमी और जल-जमाव की समस्याओं को दूर करने के लिए, सरकार ने हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण की स्थापना की है, जिसने जल स्तर के आधार पर गांवों को वर्गीकृत किया है। 1,948 गांवों को गंभीर रूप से तनावग्रस्त भूजल गांवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरी ओर, 85 गांवों को गंभीर रूप से जल-जमाव वाले गांवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तालाब प्राधिकरण

तालाब गांवों में पानी का पारंपरिक स्रोत हैं। उन्हें बहाल करने और फिर से जीवंत करने के लिए, राज्य सरकार ने हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की है। प्राधिकरण ने सभी 18,281 तालाबों का डाटा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड कर दिया है। 905 तालाबों के सुधार व जीर्णोद्धार का कार्य पूरा कर लिया गया है।

कई तालाब ऐसे हैं जिनमें गंदा पानी ही जमा होता रहता है। उनके लिए तीन तालाब की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पानी को शुद्ध किया जाता है ताकि इसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जल शक्ति अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए व्यक्तिगत जल भंडारण तालाबों के निर्माण की अनुदान सीमा को भूजल पुनर्भरण के लिए 75,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है।

हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। हरियाणा में उनके नाम से 30 से अधिक गुरुद्वारे हैं।

'म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना के तहत होली के अवसर पर प्रदेश के 23 गांवों में 24 घंटे बिजली देना शुरू किया गया है। योजना के तहत अब 5,592 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो गई है।

अयोध्या नगरी में गाली बंद घर अभियान

जींद के बीबीपुर गांव का मॉडल लागू होगा

संगीता शर्मा

अयोध्या नगरी के गांवों को भी अब हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के मॉडल को लागू करने की पहल शुरू हो चुकी है। यह महिला केंद्रित गाली से मुक्त कराने के लिए 'गाली बंद घर' अभियान से की गई है। अयोध्या के पलिया लोहानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 19 गांवों में अभियान चलाया जाएगा। देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसा प्राप्त एवं दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बीबीपुर के सरपंच रहे सुनील जागलान ने पलिया लोहानी ग्राम पंचायत को महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य के लिए गोद लिया है।

उत्तर प्रदेश के गांव बनेंगे आदर्श

सुनील जागलान ने कहा कि महिला केंद्रित गाली घरेलू हिंसा की घर में पहली नींव रखती है इसलिए हम इस अभियान को घर से शुरू कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हमें इस अभियान को लेकर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री व अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। पलिया लोहानी ग्राम पंचायत के प्रधान अभिषेक सिंह ने बताया कि अधिकांश गांवों के घरों में महिला संबंधित गाली दी जाती रही है लेकिन सुनील जागलान के प्रयास से लोगों में समझ आई है। हम बीबीपुर मॉडल को गांव में लागू कर उत्तर प्रदेश का आदर्श गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके प्रयासों से गांव में पहली बार महिला दिवस भी मनाया गया, जिससे महिलाओं में नई जागृति महसूस हुई है।

सरपंच बन सकते हैं 'ब्रांड एंबेसडर'

सुनील जागलान का कहना है कि सरपंच को केवल गांव के विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करके 'ब्रांड एंबेसडर' भी बन सकता है। उन्होंने बताया कि मेवात में लड़कियां चुनाव में नहीं खड़ी होती है, इसलिए उन्होंने वहां जाकर लड़कियों को चुनाव के लिए तैयार किया है। लड़कियां अब 'डोर टू डोर' हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रही हैं। वह चुनाव में खड़े होने के लिए भी अब सक्षम बन गई हैं। सुनील बताया कि उन्होंने सरपंचों के लिए 'गाइडेंस काउसलिंग सेंटर' भी खोला है, जिसमें वह युवा पीढ़ी को अच्छा सरपंच बनने के लिए परामर्श देती हैं।

पंचायतों को बनाया हाइटेक

सुनील जागलान ने बारह साल पहले पंचायतों को हाइटेक बनाने की जो शुरुआत अपनी पंचायत की वेबसाइट बनाकर की थी। उसे पूरे देश की पंचायतों ने अपनाया। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने सभी पंचायतों के डिजिटलाइजेशन करने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि आठ राज्यों में उनके गांव के मॉडल को अपनाया जा रहा है और वह

अलग-अलग राज्यों में जाकर महिला सशक्तिकरण व गांव के विकास का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने वर्ष 2012 में बेटी बचाओ अभियान शुरू किया एवं उनके द्वारा शुरू किए गए 'सेल्फी विद् डॉटर' अभियान की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छह बार मन की बात व अमेरिका व इंग्लैंड के कार्यक्रमों में सराहना की। इसके अलावा वर्ष 2016 में सुनील जागलान के बीबीपुर मॉडल को तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन द्वारा गोद लिए गए 100 गांवों में लागू किया और सुनील जागलान को 50 लाख रुपए का अनुदान भी दिया।

प्रेरणा बने अभियान

सुनील जागलान के अभियान बेटियों के नाम नेमप्लेट, माहवारी की ज़ागरूकता के लिए शुरू किए पीरियड चार्ट जैसे सैकड़ों अभियान अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोर चुके हैं। सुनील जागलान पर बनीं डॉक्यूमेंटरी फिल्म सनराइज़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है तथा सयुंक्त राष्ट्र द्वारा इस फ़िल्म को विश्व के 73 देशों में दिखाया जा रहा है।

छापा चित्र के उस्ताद-राहुल धीमान

प्रिंट मेकिंग यानी छापाचित्र कला एक ऐसी तकनीक है, जिसमें अनुभव और अनुमान दोनों के सहारे काम करना पड़ता है। अनुमान इसलिए कि यह सीधी प्रक्रिया नहीं है। केवल एक अनुमान के साथ ही घंटों काम के बाद के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, परिणाम प्रिंट के बाद ही पता चलता है। इसलिए यह कहना ग़लत नहीं कि प्रिंट मेकिंग पूरी तरह अनुभव और अनुमान का सुमेल है।

इसी अनुभव और अनुमान की परिपक्वता का जीवंत उदाहरण हैं अंबाला शहर के प्रिंटमेकर राहुल धीमान। उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर इन फाइन आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ आर्ट, चंडीगढ़ से 2014 में पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2017 में यूजीसी नेट और 2021 में पीएचडी के शोधलेख ललित कला विभाग, कुरुक्षेत्र से इसी साल डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर लेंगे। वे पिछले 10 सालों से प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में काम करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ आर्ट, चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

राहुल का बचपन से ही कला के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहा है। पिता रेलवे में पेंटर थे। वे जब भी कोई पेंटिंग बनाते तो राहुल उनके साथ जाकर इसे सीखने की कोशिश करते। धीरे-धीरे उनका उत्साह बढ़ने लगा और वे अपनी इस कला को निखारने लगे। इसके बाद जब उन्हें 2008 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ आर्ट, चंडीगढ़ में पढ़ने का अवसर मिला तब उनकी इस कला की शुरुआत हुई।

वे हर रोज़ अंबाला से चंडीगढ़ रेल व साइकिल से सफ़र किया करते थे। इस दौरान वे अपने आस-पास के दृश्यों को देखते और समझते अपने ज़हन में उतार कर अपनी कला में के माध्यम से दिखाया।

उनकी विशेषता प्रिंट मेकिंग यानी छापा चित्रकला है। इसमें उन्होंने अलग- अलग तरह के कई काम किए हैं। जैसे वुडकट, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, कोलोग्राफी और एचिंग इत्यादि। एचिंग प्रिंट में मुख्य रूप से लोकल इंकिंग और टॉप रोलिंग का अधिक प्रयोग करते हैं। उनकी एक बड़ी खूबी है कि वे मूर्त के साथ उसके परिवेश को समकालीन कला में बदल देते हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण रेलवे टिकट्स पर बने उनके प्रिंट हैं। उन्होंने अपने हर काम में प्रतीकात्मक रेलवे ट्रैक आम इंसान के नित्यप्रति के संघर्ष को लक्ष्य की ओर बढ़ता दिखाता है।

राहुल ने अपनी कलाकारी के बलबूते राज्य , राष्ट्रीय साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वे अभी तक अपनी कला यात्रा में 35 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। जिसमें नेशनल अवार्ड न्यू दिल्ली, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, मुंबई, अमृतसर, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, शिमला, हरियाणा राज्य पुरस्कार, चंडीगढ़ ललित कला अकादमी राज्य पुरस्कार, पंजाब ललित कला अकादमी राज्य पुरस्कार, चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की स्टेट और नेशनल स्कॉलरशिप के साथ-साथ उन्हें इसी साल ही केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से जूनियर फेलोशिप के पुरस्कार से भी नवाज़ा गया है। अभी तक वे 150 से अधिक स्टेट और नेशनल एग्जिबिशन के साथ- साथ 35 इंटरनेशनल एग्जिबिशन में भी भाग ले चुके हैं, जिनमें चाइना, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, बांग्लादेश इत्यादि शामिल हैं।

वे पिछले तीन-चार वर्षों से हरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रिंट मेकिंग सिखा रहे हैं ताकि कला के प्रति बच्चों की रुचि विकसित हो सके । वे चंडीगढ़ में भी अपना प्रिंट मेकिंग स्टूडियो शुरू करने जा रहे हैं। जिसके माध्यम से वे युवाओं और बच्चों को कला क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा।

अपनी प्रतिभा के दम पर आज राहुल ने अपने जैसे अनेक युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया है। यदि मन में कुछ करने की चाह और लगन हो तो संघर्ष करते हुए पूरे जुनून के साथ मेहनत की जाए तभी असंभव लक्ष्य सम्भव हो पाता है।

- सुरेंद्र बांसल

वर्तमान राज्य सरकार कार्यकाल के दौरान 750 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित चुकी है। अब 1,300 और ऐसी कॉलोनियों की ओर से सरकार को नियमित करने के लिए आवेदन भेजा गया है।

फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा 1,500 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में दिए गए, जबकि बीमा कंपनियों द्वारा 5,210 करोड़ रुपए दिए गए। मुआवजे के रूप में 4,729 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जा चुके हैं।

मजलिस नाथ डेरा

350 साल से चेतन है अखंड धूणा

मनोज प्रभाकर

फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की नवमी को हर वर्ष सोनीपत के गांव रभड़ा में बाबा मजलिस नाथ के डेरे पर मेला लगता है। मेले में दूर-दूराज से श्रद्धालुजन आते हैं और डेरे के घूणे पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डेरे का प्राचीन इतिहास नाना प्रकार की चमत्कारिक दंत कथाएं समेटे है। वर्तमान में डेरे की मान्यता एवं ख्याति का एकाएक विस्तार हुआ है। डेरे के आलोक में बढ़ोतरी का मुख्य कारण, यहां के गद्दीनशीन बाबा चमननाथ की कड़ी मेहनत एवं समाज के प्रति समर्पित भावना है। महंत चमननाथ करीब 35 वर्ष से यहां कर्मयोगी हैं।

मजलिसनाथ डेरा गांव की करीब पांच एकड़ भूमि में स्थित है। हर रोज सुबह पौ फटने से पूर्व करीब साढ़े चार बजे मंदिर में पूजा पाठ होती है। इस दौरान करीब पांच मिनट तक नाद, शंख व नगाड़े बजते हैं। इन वाद्यों की ध्वनि से पूरे क्षेत्र का माहौल अध्यात्मिक शक्ति से सराबोर हो जाता है।

डेरे की स्थापना के विषय में किंवदंती है कि करीब 350 वर्ष पूर्व सिद्ध बाबा मजलिस नाथ बोहर स्थित प्रमुख डेरे से एक जलता हुआ उपला लेकर चले थे। वे अपनी यात्रा पर थे, चलते-चलते उनका जलता हुआ उपला यहां की सुनसान जगह पर गिर गया। मजलिसनाथ को गुरुओं का आदेश था कि जहां उनका उपला गिरे वहीं पर धूणा लगा लेना। सो, उन्होंने इसी स्थान पर जाल के पेड़ के नीचे धूणा जमा दिया।

ग्रामीणों ने उनको कहा कि यह स्थान मृत पशुओं के लिए है इसलिए वे यहां धूणा न लगाएं लेकिन हठी बाबा ने उनकी बात न मानी। एक दिन जब एक मृत भैंस वहां लाई गई तो बाबा ने उनको एक छड़ी से डांटकर जिंदा कर दिया और वह भैंस वहां से गांव की ओर चल पड़ी।

धूणा यानी कि सुलगता हुआ गोबर का उपला। धूणे की जानकारी गांव के बाद गुहांड तक हो गई। बताते हैं उस दौरान गांव में कुछ ऐसी छुटपुट आपदा हुई कि बाबा मजलिस नाथ ने उनका अपनी सिद्धता से निवारण कर दिया। कुछ और चमत्कार हुए तो धूणे की ख्याति दूर-दूर तक फैलती चली गई। उल्लेखनीय है कि वह धूणा अखंड रूप से आज तक चेतन अवस्था में है। डेरे की भाषा में इसे 'चेतना' कहा जाता है।

बाबा मजलिस नाथ के बाद यहां मलूक नाथ, डोकल नाथ, दानी नाथ, जीतराम नाथ, टेका नाथ, बालक नाथ, मोसद्दी नाथ व बाबा रूप नाथ हुए।

बाबा मजलिसनाथ, बोहर स्थित डेरे की तीसरी पीढ़ी के गुरु माने जाते हैं। बाबा मस्तनाथ, रोहतक में बोहर डेरे के संस्थापक रहे हैं। जिनके नाम से यहां डेरे के साथ शिक्षण संस्थाओं का बड़ा केंद्र हैं। बाबा बालकनाथ जो राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, यहां के गद्दीनशीन हैं। बाबा बालकनाथ का प्रताप चारों ओर फैला है। उनकी सिद्धी का प्रमाण यह है कि उनको 'पीर' की उपाधि दी गई है। पीर उनको कहा जाता है जिनके दर्शन मात्र

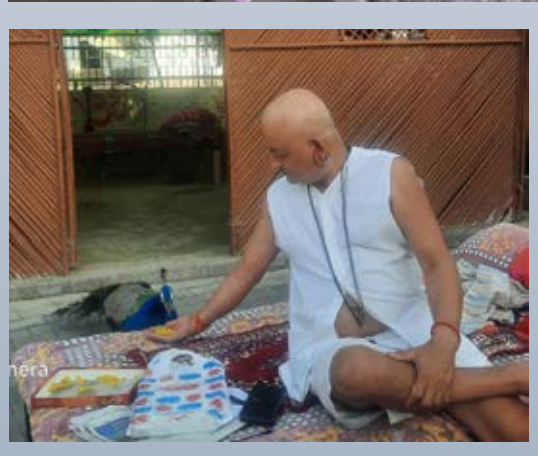

से लोगों की पीड़ा दूर होने लगती है। बाबा बालकनाथ का दर्ज़ा काफी ऊंचा है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी उनको बड़ा सम्मान देते हैं। बोहर डेरे की गरिमा गोरखपुर डेरे के समकक्ष मानी जाती है।

गांव रभड़ा स्थित बाबा मजलिसनाथ डेरे पर हाल में आयोजित मेले के अगले दिन बाबा बालकनाथ पधारे। दरअसल नवमी के अगले दिन दसवीं को डेरे पर विशेष आयोजन होता है जिसमें दूर दूराज से आए हजारों साधु संत उपस्थित होते हैं। मेले के समापन पर गद्दीनशीन बाबा की ओर से सभी मेहमानों को भावपूर्ण विदाई दी जाती है। यह एक विशेष एवं अनूठा आयोजन होता है।

जमात यानी प्रबंधन समिति

डेरों के इस तरह के विशेष आयोजनों के प्रबंधन के लिए सम्प्रदाय के पास एक विशेष सुरक्षा दस्ता है। जिसे 'जमात' कहा जाता है। जमात के प्रमुख का सम्प्रदाय में इतना बड़ा दर्ज़ा होता है जितना किसी सेना के जनरल का होता है। यह जमात पूरे देश में काम करती है। फिलहाल इसके दो प्रमुख हैं। 'बारह' के प्रमुख बाबा कृष्णनाथ जी व 'अट्ठारह' के प्रमुख बाबा सोमनाथ जी हैं। इनकी नियुक्ति 12-12 वर्ष के लिए होती है। सम्प्रदाय चाहे तो इनका सेवाकाल बढ़ा सकता है।

नाथ सम्प्रदाय का फैलाव भारत में राजस्थान से लेकर गंगासागर तक व उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। नेपाल, तिब्बत व चीन में भी इसका विस्तार एवं मान्यता है। बाबा चमननाथ बताते हैं कि इसका संबंध केवल हिंदू धर्म से नहीं है, अन्य धर्मों के साधु संत व आम लोग भी इसमें आस्था रखते हैं।

वे बताते हैं जमात केवल आयोजनों तक सीमित नहीं है। पूरे सम्प्रदाय में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी डेरे में किसी साधु संत के प्रति कोई शिकायत होती है तो जमात में उनकी तारीख पड़ती है। दोनों ओर की सुनवाई होती है और समाधान होता है। अनुशासनहीनता या दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान भी है।

योगियों की खास परंपरा

नाथ साधु-सन्त परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे 'सिले' कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। योगी दो तरह के होते हैं। औघड़ व दर्शनी। बाबा चमननाथ बताते हैं कि औघड़ के कान में छिद्र नहीं होता जबकि दर्शनी बाबा के कानों में कुंडल होते हैं। बाबाओं में आठ पद होते हैं तथा पांच तरह के गुरु होते हैं, जिनकी उपाधि पारिवारिक व्यवस्था के तहत तय होती है।

बाबा चमननाथ कहते हैं कि जिस प्रकार सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने सन्यास से गृहस्थ में प्रेवश किया उसी प्रकार उनके सिद्धों ने समाज के बीच रहकर समाज का कल्याण किया और करते आ रहे हैं। इसलिए यह कहना भ्रामक है कि सन्यासियों को समाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

भगवान शंकर को माना गया आदिगुरु

मध्ययुग में उत्पन्न इस सम्प्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परम्पराओं का समन्वय दिखायी देता है। यह हठयोग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस सम्प्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य माने जाते हैं।

आदिगुरू भगवान शंकर को माना गया है। उनके बाद मच्छेन्द्रनाथ जी हैं जो 8 वीं या 9वीं सदी के योग सिद्ध बाबा माने जाते हैं। उनके बाद गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) रहे जिन्हें 10वीं या 11वीं शताब्दी में जन्म, मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक, व्यवस्थित योग तकनीकों, संगठन , हठ योग के ग्रंथों के रचियता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध मान्यता है।

जालन्धरनाथ, 12वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से जालंधर (पंजाब) निवासी, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त रहे। उनके बाद कानीफनाथ, 14वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से बंगाल निवासी, नाथ सम्प्रदाय के भीतर एक अलग उप-परंपरा की शुरूआत करने वाले साधु माने गए। चौरंगीनाथ, बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर-पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त, उनसे संबंधित एक तीर्थस्थल सियालकोट (अब पाकिस्तान में) में है।

चर्पटीनाथ, हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले, उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया और बताया कि व्यक्ति को अपनी आन्तरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। भर्तृहरिनाथ, उज्जैन के राजा और विद्वान जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। गोपीचन्दनाथ, बंगाल की रानी के पुत्र जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। रत्ननाथ, 13वीं सदी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्यातिप्राप्त, उत्तर भारत में नाथ और सूफी दोनों सम्प्रदाय में आदरणीय रहे। धर्मनाथ, 15वीं सदी के सिद्ध, गुजरात में ख्यातिप्राप्त, उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की थी, किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कच्छ क्षेत्र को जीवित रहने योग्य बनाया। बाबा मस्तनाथ, 18वीं सदी के सिद्ध, उन्होंने हरियाणा के बोहर में मठ की स्थापना की।

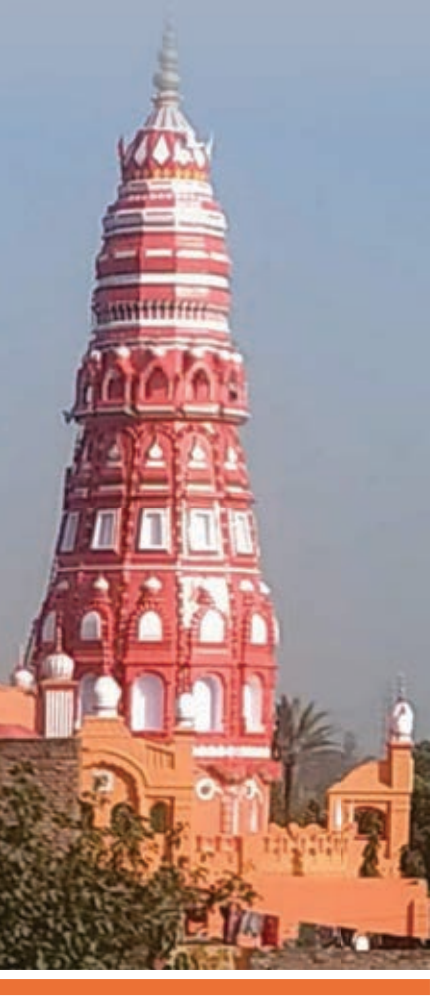

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार कपास उत्पादन का खरीफ 2022 सीजन के लिए 19.25 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत सहकारी क्षेत्र में जींद और सिरसा के दो दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए परियोजना लागत को स्वीकृति प्रदान की है।

सूरजकुंड मेले में दिखा संस्कृति का संगम

कश्मीर से वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना घर, हाउस बोट का लाइव प्रदर्शन और स्मारक द्वार 'मुबारक मंडी-जम्मू' की प्रतिकृतियां मुख्य आकर्षण रही। साथ ही, जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों कलाकारों ने विभिन्न लोक कलाओं और नृत्यों का प्रदर्शन किया। पारंपरिक नृत्य कला रूपों से लेकर उत्कृष्ट शिल्प तक, जम्मू-कश्मीर की विरासत और संस्कृति का एक गुलदस्ता विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण रहा।

संगीता शर्मा

फरीदाबाद के अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का सैलानियों को प्रतिवर्ष बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन कोविड महामारी के कारण गत दो वर्ष मेला आयोजित नहीं किया जा सका। लंबे अंतराल के बाद 19 मार्च को 35 वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ। चार अप्रैल तक आयोजित इस मेले में जहां सैलानियों ने शिल्पकारों की नायाब कलाकृतियां खरीदी, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जमकर लुत्फ उठाया। मेले का क्षेत्र 43.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और शिल्पकारों के लिए 1,183 वर्क हट्स और एक बहु-व्यंजन फूड कोर्ट में सैलानियों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा चखा। मेले का माहौल महुआ, नरगिस, पांचजन्य जैसे रूपांकनों और सजावट के साथ जातीय जीवंतता पर ले गया।

लोक कलाकारों का शानदार प्रदर्शन

सैलानियों के मूड को जीवंत करने के लिए भारत के राज्यों के कलाकारों सहित भाग लेने वाले विदेशों के अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकारों द्वारा शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पंजाब के भांगड़ा, असम के बीहू, बरसाना की होली, हरियाणा के लोक नृत्य, हिमाचल प्रदेश के जमाकड़ा, महाराष्ट्र का लावणी, हाथ की चक्की का लाइव प्रदर्शन और हमेशा से मशहूर रहे बेहरुपिया जैसे विभिन्न प्रकार के कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, लेबनान, सूडान, ट्यूनिशिया, घाना, मोजांबिक, नेपाल आदि देशों से आए शिल्पकारों व दस्तकारों के पांडाल दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

छोटी चौपाल पर हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, उत्तरी भारत सांस्कृतिक जोनल तथा विदेश से आए कलाकार अपने हुनर और नृत्य की अदाओं से दर्शकों का दिल जीता। उत्तराखंड के युवक-युवतियों ने कुमांऊ अंचल का छपेली लोकनृत्य प्रस्तुत किया। हरियाणा के जादूगर अशोक सम्राट की करामातों ने दर्शकों को दांतों तले ऊंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। राकेश भराणिया की रागनी 'पाणी आली पाणी प्या दे, ठा के डोल खड़ी होगी..' को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया।

छोटी चौपाल ने मचाई धमाल

शहीदी दिवस के दिन अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरू व सहदेव की याद में दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें याद किया गया। उसके बाद सांस्कृतिक रंग जमाने में छोटी चौपाल ने पूरे मेले में धमाल मचाया हुआ है। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश व उनके साथी मित्रों का चौपाल पर फूलों से स्वागत किया गया। बाद में सम्मानस्वरूप उनको पगड़ी बांधी गई। मुख्य अतिथि के समक्ष राजेंद्र वर्मा व उनके साथी कलाकारों ने तुंबा, घड़वा, बैंजो, नक्कारी, ताशा, डमरू, डेरू, बंसरी, हारमोनियम, ढोल, घुंघुरू, खड़ताल आदि साजों के साथ हरियाणवी आर्केस्ट्रा की शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा लड़कियों का लोकनृत्य बागां मैं बोले मोर..गीत पर शानदार रहा। अनादि ग्रुप की प्रस्तुति, शिव तांडव, पाणी आली पाणी प्या दे रागनी, केसरिया बालमा पधारो म्हारे देस..इथोपिया लोक कलाकारों का जानदार नृत्य ने भी दर्शकों का भरपूर प्यार पाया।

बंदियों की ओर से लगी स्टॉल

मेले में जिला जेल की स्टॉल नंबर-787 पर लोगों ने जमकर खरीददारी की। जिला जेल की स्टॉल पर बंदियों द्वारा बनाई गई दीवार घड़ी, मिरर, पेंटिंग, झूला, मंदिर, जूट बैग, ग्रीटिंग कार्ड, पत्थर कुंडल, चरखा, ऐश-ट्रे, रिमोर्ट स्टैंड, पैन स्टैंड, शीशा फ्रेम, निवार बेल्ट, फाइल कवर, पर्स, चाबी स्टैंड, फोन स्ट्रेरी, गणेश प्रतिमा, महिला स्टैचू, कुर्सी, मूढा सहित अनेक चीजें लोगों का आकर्षण का केंद्र बनीं।

जम्मू कश्मीर 'थीम स्टेट'

चूंकि जम्मू एवं कश्मीर 35वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का 'थीम स्टेट' है, इसलिए वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर,

परंपरा, विरासत और संस्कृति की त्रिवेणी

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में आयोजित 35वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश की हस्तशिल्प, हथकरघा परंपरा को प्रदर्शित करने वाले इस मेले में उपस्थित होना गर्व की बात है। उन्होंने आजादी के अवसर पर इस मेले के आयोजन के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार को बधाई व शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिल्प व हथकरघा मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद व कला के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। इस उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला पिछले 35 सालों से ऐसे ही शिल्पकार, हथकरघा कारीगरों को एक उचित मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस मेले का आयोजन एक 'थीम स्टेट' और एक सहभागी देश के साथ किया जाता है। इस वर्ष मेले का 'थीम स्टेट' केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और सहभागी देश उज्बेकिस्तान है।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com